CEASI TIMES

11th August 2025

HINDI

Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

ASCI
Agriculture Skill Council of India

CEASI
CENTRES OF EXCELLENCE FOR AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

CEDSI
CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAIRY SKILLS IN INDIA

CEFMI
Centre of Excellence for Farm Mechanization Skills in India

CEHSI
Centre of Excellence for Horticulture Skills in India

www.ceasi.in

हमारे बारे में

हम कौन हैं:

"सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEASI)" एक स्वायत्त संस्था है, जो "एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI)" के अधीन कार्य कर रही है। यह संस्था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत किसानों, मजदूरी श्रमिकों, स्वरोजगार में लगे पेशेवरों, विस्तार कार्यकर्ताओं आदि के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण का कार्य करती है।

CEASI कृषि के विभिन्न उप-क्षेत्रों में स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की शीर्ष संस्था है, जैसे कि:

- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेयरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEHSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेकनाइजेशन स्किल्स इन इंडिया (CEFMI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर (CoE-CRA)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर (CoE-AI)

हम क्या करते हैं:

- **कौशल विकास और क्षमता निर्माण:** कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में हितधारकों की आवश्यकताओं के आधार पर क्षमता निर्माण।
- **ज्ञान प्रबंधन:** वर्कफोर्स मानकों को समर्थन देने हेतु QPs, NOS, स्किल गैप रिपोर्ट और न्यूज़लेटर्स का विकास।
- **अनुसंधान:** उद्योग की मांगों के अनुसार आवश्यकताओं की पहचान और कौशल अंतर को पाटने के लिए अनुसंधान।
- **नीति समर्थन और परामर्श सेवाएं:** नवाचार साझा करने और क्षेत्रीय चुनौतियों को हल करने हेतु नेटवर्क का निर्माण।

हमारा विज़न

एक स्वायत्त उत्कृष्टता संस्थान जो कृषि में उच्च कौशलयुक्त कार्यबल विकसित करने के लिए समर्पित है, नवाचार, तकनीकी प्रगति और सतत प्रथाओं के माध्यम से भारतीय कृषि की समृद्धि और लचीलापन बढ़ाने के लिए कार्यरत है।

हमारा मिशन

राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उन्नत कृषि पद्धतियों में कौशल विकास के लिए अग्रणी संगठन के रूप में उभरना, जो सततता, लाभप्रदता, क्षमता निर्माण, ज्ञान प्रसार, नीति समर्थन और नवाचार आधारित अनुसंधान के माध्यम से कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करता है।

CEASI का प्रभाव:

CEASI भारतीय कृषि में एक परिवर्तनकारी बदलाव ला रहा है, जो व्यक्तियों को सशक्त बनाने, कौशल को निखारने और देशभर में समुदायों को उन्नत करने का कार्य कर रहा है।

- 15+ राज्य
- 15 एफपीओ को प्रशिक्षित और सहयोग प्रदान किया गया
- 20,000 कृषि / डेयरी पेशेवरों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया
- 5000+ उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया
- 3000+ महिलाओं को सशक्त बनाया गया
- 30,000+ जीवन को प्रभावित किया गया

उत्तर प्रदेश में किसानों को ई-लॉटरी से सब्सिडी पर कृषि उपकरण वितरण

उत्तर प्रदेश सरकार 7 और 8 अगस्त को किसानों को सब्सिडी पर कृषि उपकरण वितरित करेगी। यह वितरण ई-लॉटरी प्रणाली से सभी 75 जिलों में जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में होगा।

कृषि विभाग के पोर्टल पर पहले से किसानों ने विभिन्न योजनाओं के तहत उपकरण बुक कराए हैं। इनमें फसल अवशेष के इन-सीटू प्रबंधन हेतु कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा और उप-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन जैसी योजनाएं शामिल हैं, जिनका उद्देश्य कार्यकुशलता बढ़ाना और कटाई के बाद की समस्याओं को कम करना है।

इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स (ऑयलसीड्स) योजना के तहत मिनी ऑयल मिल एक्सट्रैक्शन यूनिट और तिरपाल की भी बुकिंग की गई है।

ई-लॉटरी से वितरण का उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना और सभी पात्र किसानों को समान अवसर देना है। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्यक्रम किसानों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराकर श्रम कम करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद क

भारत में डीप-टेक नवाचार और औद्योगिक ढांचा मजबूत

भारत का डीप-टेक क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है, जिसमें बेंगलुरु स्थित के टेक, मेइटी, नैसकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी साझेदारियां अहम भूमिका निभा रही हैं। यह देश के सबसे बड़े नवाचार केंद्रों में से एक है, जो स्टार्टअप, उद्योग, शैक्षणिक संस्थान और सरकार को जोड़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, एआर/वीआर और बिग डेटा जैसे उन्नत समाधानों पर काम करता है।

ये तकनीकें विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर में दक्षता और प्रतिस्पर्धा बढ़ा रही हैं।

साथ ही, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 1,736 एकड़ में फैला तुमकुरु औद्योगिक क्षेत्र लगभग तैयार है। यहां आंतरिक सड़कें, जलनिकासी और यूटिलिटी कॉरिडोर जैसी सुविधाएं निवेश के लिए उपलब्ध होंगी।

मजबूत नीतिगत सहयोग, राज्य-केंद्र समन्वय और डिजिटल ढांचे के साथ भारत नवाचार-आधारित विनिर्माण और निर्यात में वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में उसकी भूमिका और मजबूत होगी।

आईसीएआर-सीआईएई ने कृषि मशीनीकरण के 44 वर्ष पूरे किए

आईसीएआर–केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान (सीआईएई), भोपाल ने कृषि मशीनीकरण में अपनी उपलब्धियों के 44 वर्ष पूरे किए और इस अवसर पर दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया।

विशेषज्ञों ने रोबोटिक्स, प्रिसिजन फार्मिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष तकनीक और नैनो टेक्नोलॉजी जैसी उन्नत तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की, जो विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए भविष्य की खेती को बदल सकती हैं।

संस्थान ने कृषि यंत्र कस्टम हायरिंग सेंटर, सोया प्रोसेसिंग यूनिट, उन्नत मशीनरी परीक्षण सुविधाएं और किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी उपलब्धियां प्रदर्शित कीं।

कृषक समृद्धि हेतु कृषि मशीनीकरण थीम पर आयोजित 'एग्री-टेक-एक्सपो' में देशभर से 40 प्रदर्शकों ने आधुनिक ट्रैक्टर, औजार और प्रोसेसिंग मशीनरी प्रदर्शित की।

अकादमिक-उद्योग संवाद में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने गुणवत्ता मानक, परीक्षण प्रणाली, उन्नत निर्माण तकनीक और अनुसंधान से खेत तक तकनीक पहुंचाने के तरीकों पर चर्चा की। यह आयोजन सीआईएई की नवाचार, सहयोग और क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

पीएयू ने कृषि अधिकारियों को पराली प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) ने पराली जलाने की समस्या को रोकने के लिए "ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स ऑन पैडी स्ट्रॉ मैनेजमेंट" कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें जालंधर, कपूरथला, मोगा, संगरूर और पटियाला सहित 11 जिलों के कृषि अधिकारी शामिल हुए।

प्रशिक्षण में धान अवशेष प्रबंधन के इन-सीटू और एक्स-सीटू दोनों तरीके सिखाए गए। अधिकारियों ने हैप्पी सीडर, सुपर एसएमएस, पीएयू स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर, सतही सीडर, बेलर और स्ट्रॉ इनकॉरपोरेशन मशीन जैसे उपकरणों का संचालन सीखा।

इसके अलावा, बायो-सीएनजी उत्पादन, स्लरी उपयोग और बायो-डीकंपोज़र जैसे टिकाऊ विकल्पों पर चर्चा हुई।

विशेषज्ञों ने सामुदायिक भागीदारी की अहमियत बताई और अधिकारियों से किसानों, स्थानीय नेताओं और महिलाओं को जागरूक करने का आग्रह किया।

इस पहल का उद्देश्य वायु प्रदूषण कम करना, मिट्टी की सेहत सुधारना और स्वच्छ खेती को बढ़ावा देना है। शेष जिलों के अधिकारियों के लिए दूसरा प्रशिक्षण सत्र 11 अगस्त को होगा।

हिमाचल के स्कूलों में व्यावसायिक विषय के रूप में बागवानी की शुरुआत

हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बागवानी को व्यावसायिक विषय के रूप में शामिल करने की घोषणा की है, जिससे छात्रों को रोजगारोन्मुख शिक्षा के अवसर मिल सकें। इसके लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम तैयार कर दो सप्ताह में प्रस्तावित किया जाएगा। साथ ही, कॉलेजों में महत्वपूर्ण शैक्षणिक विषयों को पुनर्जीवित करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि छात्रों को विषयों की व्यापक पसंद मिल सके। राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल और अटल आदर्श विद्यालय जैसी प्रमुख योजनाओं की समीक्षा में रिक्त पदों की शीघ्र भर्ती पर बल दिया गया, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ सके।

विभाग ने कॉलेजों के लिए पुस्तकालयों को सुसज्जित करने, एनएएसी मूल्यांकन समय पर पूरा करने और दूरस्थ व जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों के योगदान को मान्यता देने को प्राथमिकता दी है। हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं से लगभग 510 शैक्षणिक संस्थान प्रभावित हुए हैं, जिनमें लगभग ₹30 करोड़ का नुकसान हुआ है। पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट से प्राप्त धनराशि का उपयोग गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त स्कूलों को प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा। मरम्मत और पुनर्स्थापना कार्य की समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण पूर्ति के लिए नियमित भौतिक निगरानी की जाएगी।

विरुधुनगर में बागवानी विकास के लिए ₹77.17 लाख स्वीकृत

राज्य बागवानी विकास योजना के तहत विरुधुनगर जिले में प्रमुख बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए ₹77.17 लाख की स्वीकृति दी गई है। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक सब्जियों, मिर्च, नारियल और फूलों की खेती का क्षेत्रफल बढ़ाना है। पारंपरिक सब्जियों के लिए ₹24,000 प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे 45 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए ₹10.80 लाख आवंटित किए गए हैं।

इसी तरह, मिर्च और नारियल की खेती के लिए ₹12,000 प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी दी जाएगी, जिसे 10-10 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तारित किया जाएगा, और इसके लिए कुल ₹24 लाख आवंटित हैं। फूलों की खेती 75 एकड़ तक बढ़ाई जाएगी, जिसके लिए ₹9 लाख की सब्सिडी निर्धारित है। कुल ₹43.80 लाख की राशि किसानों को फसल विस्तार के लिए सब्सिडी के रूप में वितरित की जाएगी। यह योजना कृषि आय बढ़ाने, फसलों में विविधता लाने और जिले के बागवानी क्षेत्र को सशक्त बनाने में सहायक होगी।

लगातार दूसरे वर्ष बलांगीर से दुबई को ड्रैगन फ्रूट का निर्यात

लगातार दूसरे वर्ष, ओडिशा के बलांगीर जिले का ड्रैगन फ्रूट अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंचा है, जिसकी ताज़ा खेप दुबई भेजी गई। पटनागढ़ में उगाई गई 330 किलो की खेप ₹300 प्रति किलो के भाव पर बिकी, जो पिछले वर्ष की कीमत से 20% अधिक है। यह उपलब्धि उच्च मूल्य वाली, बाज़ार केंद्रित बागवानी में ओडिशा की बढ़ती पहचान और वैश्विक बाजार में गुणवत्ता व स्थिरता के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को दर्शाती है।

यह ड्रैगन फ्रूट जैविक तरीके से उगाया गया था और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के माध्यम से प्राप्त किया गया, जिन्हें कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन पहलों का उद्देश्य किसानों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना, फसल की गुणवत्ता सुधारना और नए विपणन अवसर उपलब्ध कराना है। ऐसे निर्यात की लगातार सफलता न केवल किसानों की आय में वृद्धि करती है, बल्कि प्रीमियम बागवानी उत्पादों के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में राज्य की साख को भी मजबूत बनाती है।

हॉर्टिकल्चर विभाग श्रीनगर ने प्रगतिशील किसानों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया

श्रीनगर में हॉर्टिकल्चर विभाग ने होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम (HADP) के तहत हॉर्टिकल्चर कॉम्प्लेक्स, लालमंडी में क्षमता निर्माण कार्यक्रम (CBP) आयोजित किया। जिले के विभिन्न बागवानी क्षेत्रों से 50 से अधिक प्रगतिशील बागवानों ने इसमें भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य आधुनिक बागवानी तकनीकों में कौशल और ज्ञान बढ़ाना था। प्रतिभागियों को विभाग की नई शुरू की गई योजनाओं की जानकारी दी गई, जो उत्पादन बढ़ाने, फसल की गुणवत्ता सुधारने और किसानों की आय में वृद्धि पर केंद्रित हैं।

कार्यक्रम के दौरान किसानों को नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे उनकी आजीविका मजबूत हो सके और बागों का सतत प्रबंधन सुनिश्चित हो। प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से व्यावहारिक जानकारी प्रदान की गई, साथ ही प्रतिभागियों को वर्मी-कंपोस्ट और बागवानी उपकरण किट वितरित किए गए ताकि वे अपने खेत स्तर के कार्यों को और बेहतर बना सकें। यह पहल क्षेत्र में बागवानी के विकास, बेहतर उत्पादन, उच्च गुणवत्ता वाली फसल और बाज़ार प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की दिशा में विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

नमक्कल में 90 करोड़ रुपये का आधुनिक डेयरी प्लांट लगभग तैयार

तमिलनाडु के नमक्कल में 90 करोड़ रुपये की लागत से एक आधुनिक डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट बन रहा है, जो 2025 के अंत तक पूरा हो जाएगा। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) द्वारा समर्थित यह प्लांट 80% तैयार हो चुका है और नवंबर 2025 में इसका परीक्षण शुरू होगा। जनवरी 2026 से यह पूरी क्षमता के साथ काम करेगा। पूरी तरह स्वचालित यह संयंत्र रोजाना 2 लाख लीटर दूध प्रोसेस करेगा। इससे 15,000 से अधिक किसानों को लाभ होगा, लगभग 1,000 अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे और 4 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं तक उत्पाद पहुंचेंगे। यह प्लांट दूध की बर्बादी कम करेगा, भुगतान समय पर सुनिश्चित करेगा और उत्पादन क्षमता बढ़ाएगा। अधिकारियों के अनुसार, यह परियोजना भविष्य के डेयरी ढांचे के लिए एक उदाहरण बन सकती है। यह पहल तमिलनाडु में कृषि प्रोसेसिंग सुविधाओं को आधुनिक बनाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा है।

एएचआईडीएफ परियोजनाएं पशुपालन और डेयरी ढांचे को मजबूत कर रही हैं

एनिमल हसबेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (AHIDF) ने देशभर में 14,413.88 करोड़ रुपये की 402 परियोजनाओं को मंजूरी दी है ताकि पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके। इस योजना के तहत 8 साल तक 3% ब्याज में छूट, 2 साल की मोहलत और परियोजना लागत का 90% तक ऋण दिया जाता है। इसके अलावा, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत 6,776.80 करोड़ रुपये की 37 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। इन परियोजनाओं में डेयरी और मीट प्रोसेसिंग, चारा संयंत्र, वैक्सीन/दवा इकाइयां, कचरे से संसाधन बनाने वाली इकाइयां और नस्ल सुधार फार्म शामिल हैं। इनसे 214 लाख लीटर प्रतिदिन दूध क्षमता बढ़ेगी, 43,000 से अधिक रोजगार बनेंगे और 25 लाख किसान लाभान्वित होंगे। 2020 से 2026 तक इसके लिए 679.5 करोड़ रुपये का बजट तय है। अधिकारी मानते हैं कि इससे मूल्य संवर्धन, आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता और टिकाऊ पशुपालन पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा

बिहार में पांच नए डेयरी प्लांट से क्षमता में वृद्धि होगी

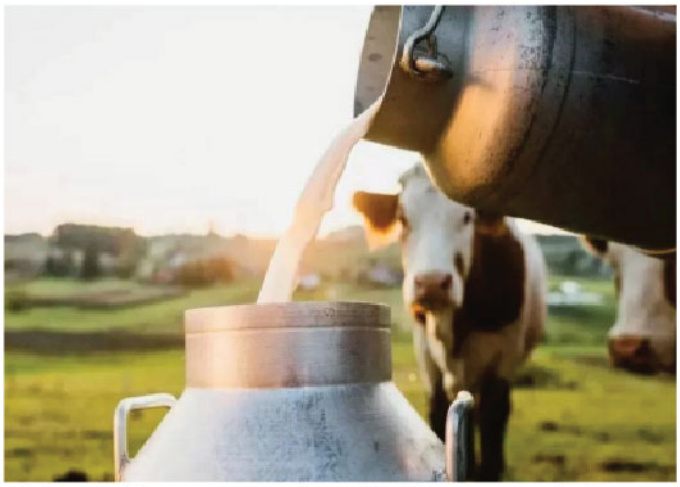

बिहार कैबिनेट ने 316 करोड़ रुपये की लागत से पांच नए डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट बनाने की मंजूरी दी है। इसका मकसद ग्रामीण डेयरी ढांचे को मजबूत करना और दूध उत्पादन बढ़ाना है। इस योजना के तहत दो बड़े प्लांट दरभंगा और वजीरगंज (गया) में बनेंगे जिनकी क्षमता 2 लाख लीटर प्रतिदिन होगी। गोपालगंज में 1 लाख लीटर प्रतिदिन का एक प्लांट और देहरी-ऑन-सोन (रोहतास) व सीतामढ़ी में 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता वाले दो मिल्क पाउडर संयंत्र बनाए जाएंगे। परियोजना को एसआईडीबीआई क्लस्टर डेवलपमेंट फंड से वित्तीय सहायता मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा, दूध व दूध उत्पादों की आपूर्ति स्थिर रहेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह योजना सहकारी नेटवर्क को मजबूत करने और बिहार की डेयरी क्षमता को पूरी तरह उपयोग करने में मदद करेगी।

घी और मक्खन पर जीएसटी घटाने की मांग

डेयरी उद्योग ने घी और मक्खन पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने की मांग की है। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि ये उत्पाद न सिर्फ पोषण के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी खास स्थान रखते हैं। उनका मानना है कि ज्यादा कर दर से कीमतें बढ़ती हैं, मिलावट को बढ़ावा मिलता है और ग्रामीण आजीविका प्रभावित होती है। कई देशों जैसे यूरोपीय संघ, अमेरिका और न्यूजीलैंड में इन उत्पादों पर या तो टैक्स बहुत कम है या बिल्कुल नहीं। दर कम करने से किसानों की आय बढ़ेगी, उपभोक्ताओं के लिए कीमतें सस्ती होंगी और बाजार में पारदर्शिता आएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे खपत बढ़ेगी, पूरी डेयरी आपूर्ति श्रृंखला को लाभ होगा और दीर्घकाल में कर अनुपालन भी बेहतर होगा। यह बदलाव राजस्व और सार्वजनिक हित दोनों को संतुलित करने में मदद कर सकता है।

केरल ने जलवायु-लचीला कृषि योजना शुरू की

केरल ने जलवायु-लचीला और ऊर्जा-कुशल कृषि (CREEA) रिपोर्ट जारी की है, जिसका उद्देश्य छोटे किसानों को केंद्र में रखते हुए समावेशी, कम-कार्बन कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र को चरम मौसम के प्रभावों से सुरक्षित करना है। योजना में पाँच प्रमुख रणनीतियाँ शामिल हैं—एकीकरण और अभिसरण योजना, जोखिम एवं आपात योजना, जलवायु-लचीली कृषि प्रणाली, नेट-ज़ीरो कृषि एवं ऊर्जा दक्षता, और क्षमता निर्माण। एक प्रमुख पहल के तहत पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर केरल क्लाइमेट-रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर इनोवेशन लैब्स (K-CRAIL) स्थापित किए जाएंगे, ताकि सतत खेती, सूक्ष्म सिंचाई और लचीली फसलों को बढ़ावा दिया जा सके। प्रारंभिक लैब्स अलप्पुझा, पलक्कड़ और वायनाड में 2026 की शुरुआत तक स्थापित की जाएंगी।

योजना में किसान बीज और जैव संसाधन नेटवर्क, सामुदायिक बीज बैंक और एक एआई-संचालित जोखिम मानचित्रण प्लेटफ़ॉर्म विकसित करने का भी प्रावधान है, जो मौसम, फसल और बाज़ार से जुड़ा वास्तविक समय का डेटा प्रदान करेगा। इन उपायों का लक्ष्य कृषि का कार्बन पदचिह्न कम करना, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना और किसानों को सतत कृषि पद्धतियाँ अपनाकर बदलते बाज़ार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाना है।

कृषि, एआई और तकनीकी क्षेत्रों में हरियाणा का इज़राइल से सहयोग

हरियाणा ने इज़राइल के साथ कृषि प्रौद्योगिकी, उन्नत सिंचाई प्रणाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपशिष्ट जल प्रबंधन, शोध और स्वास्थ्य सेवाओं सहित कई क्षेत्रों में सहयोग करने की योजना बनाई है। चर्चाओं में राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, हिसार में इंटीग्रेटेड एविएशन हब के विकास और विदेशी रोजगार अवसरों के विस्तार पर भी जोर दिया गया। विदेशी सहयोग विभाग राज्य के युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय रोजगार अवसर बढ़ाने और निर्यात को दोगुना करने की दिशा में कार्यरत है। वर्तमान में 180 से अधिक युवा इज़राइल में कार्यरत हैं, जबकि इज़राइल के स्वास्थ्य क्षेत्र में 5,000 नर्सों की मांग है।

राज्य में एक वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित करने की भी योजना है, जिससे युवाओं को आधुनिक एआई कौशल में प्रशिक्षित किया जा सके और नवाचार को प्रोत्साहन मिले। इसके साथ ही, अपशिष्ट जल को सिंचाई के लिए पुन: उपयोग करने और इसे कृषि व पेयजल के लिए उपयुक्त बनाने की नई तकनीकों पर भी इज़राइल के साथ कार्य किया जाएगा। ये पहलें आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और कौशल विकास को बढ़ावा देंगी।

वैश्विक सम्मेलन में एम.एस. स्वामीनाथन की शताब्दी, टिकाऊ कृषि पर फोकस

नई दिल्ली में प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन की 100वीं जयंती पर एम.एस. स्वामीनाथन सेंचुरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। प्रोफेसर स्वामीनाथन को भारत की हरित क्रांति और कृषि विज्ञान के वैश्विक नेता के रूप में जाना जाता है।

एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और राष्ट्रीय कृषि संस्थानों द्वारा आयोजित तीन दिवसीय सम्मेलन का विषय था – "एवरग्रीन रेवोल्यूशन – द पाथवे टू बायो-हैप्पीनेस"। इसमें वैज्ञानिकों, नीति-निर्माताओं, विकास विशेषज्ञों और विभिन्न हितधारकों ने कृषि को टिकाऊ, जलवायु-लचीला और पोषण-संवेदनशील बनाने के तरीकों पर चर्चा की।

मुख्य विषयों में जैव विविधता का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग, तकनीक आधारित आजीविका समाधान, और कृषि में महिलाओं व युवाओं की भागीदारी शामिल रहे।

वक्ताओं ने स्वामीनाथन के फसल उत्पादकता बढ़ाने, जैव विविधता को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के योगदान को याद किया।

सम्मेलन में विषयगत सत्र, ज्ञान-विनिमय और एक भूख-मुक्त व टिकाऊ भविष्य के लिए रणनीतियों पर चर्चा हुई।

नीति आयोग ने जीएम फसल आयात पर पेपर वापस लिया, जैव सुरक्षा पर जोर

नीति आयोग ने एक पेपर वापस ले लिया जिसमें अमेरिका से जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) सोयाबीन और मक्का आयात करने का सुझाव था। यह फैसला ऐसे समय आया है जब देश में ट्रांसजेनिक खाद्य फसलों की जैव सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। पेपर में कहा गया था कि इनका आयात घरेलू उत्पादन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन सरकार ने सावधानी बरतने का फैसला किया। भारत में जीएम फसलों पर कड़े नियम हैं और इन्हें अपनाने से पहले उनके स्वास्थ्य, पर्यावरण और जैव विविधता पर असर का पूरा वैज्ञानिक परीक्षण जरूरी है। इस कदम से यह भी साफ होता है कि देश आत्मनिर्भरता और स्थानीय बीजों को बढ़ावा देना चाहता है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि जीएम तकनीक पर दुनिया में बहस जारी है, लेकिन भारत की नीति यही है कि किसी भी तकनीक को अपनाने से पहले उसके दीर्घकालिक असर को ध्यान से परखा जाए। यह निर्णय कृषि में टिकाऊ और सुरक्षित तरीकों पर फोकस को दर्शाता है

सीईएचएसआई गोलमेज बैठक – स्मार्ट पोस्ट-हार्वेस्ट रणनीतियाँ

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEHSI) ने 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक दिवसीय गोलमेज बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की। इस बैठक का विषय था – "स्मार्ट पोस्ट-हार्वेस्ट रणनीतियाँ: मूल्य वृद्धि, नुकसान में कमी और आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता"।

हम देश डिलाइट (Country Delight) को कार्यक्रम प्रायोजक के रूप में और अपने ज्ञान साझेदार – निफ्टेम (NIFTEM) और महाराणा प्रताप उद्यानिकी विश्वविद्यालय (MHU) – को उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं। साथ ही हमारे संस्थागत साझेदार एनएसएफआई (NSFI) और डेलावल (DeLaval) का निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एमएचयू के कुलपति डॉ. एस.के. मल्होत्रा, तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त आयुक्त डॉ. नवीन पाटले, भारतीय पैकेजिंग संस्थान के अतिरिक्त निदेशक डॉ. तनवीर आलम, एचटीआई के प्राचार्य डॉ. जोगिंदर सिंह, एएससीआई के सीईओ डॉ. सतेंद्र सिंह आर्य और एनएसएफआई के सीईओ डॉ. साई कृष्ण उपस्थित रहे।

सीआईआई फेस, फिक्की, यूपीएल, ग्रांट थॉर्नटन, मदर डेयरी, आईसीएआर, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, ट्रॉपिकल एग्रो, आयकार्ट, एनएएफपीओ, नॉर्दर्न फार्मर मेगा एफपीओ और अन्य प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी की।

बैठक में पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान कम करने, कोल्ड चेन ढांचे को मजबूत करने, खेत स्तर पर मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने और टिकाऊ पैकेजिंग के माध्यम से शेल्फ लाइफ बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।

हमारा लक्ष्य है कि कौशल विकास, तकनीक और सहयोग के माध्यम से एक स्मार्ट और मजबूत उद्यानिकी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जाए।

अयोध्या में 'सश्वत मिठास' पहल के तहत टिकाऊ गन्ना खेती को बढ़ावा

'सश्वत मिठास' पहल के तहत, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया और UPL SAS लिमिटेड मिलकर अयोध्या में टिकाऊ (सस्टेनेबल) गन्ना खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। अब तक 431 किसानों का सर्वे किया गया है, जिसमें 69 असंगठित और 3 संगठित किसान समूह शामिल हैं। इस सर्वे से मिली जानकारी के आधार पर गांव स्तर पर डेमोंस्ट्रेशन प्लॉट तैयार किए गए हैं, जहां पानी के कुशल उपयोग, मिट्टी की सेहत सुधारने और जैविक खाद/इनपुट के प्रयोग जैसी बेहतरीन तकनीकें दिखाई जा रही हैं।

समुदाय की भागीदारी और आपसी सीख को बढ़ावा देने के लिए टीम ने 73 रिटेलर मीटिंग, 8 फील्ड डे और 459 किसानों से व्यक्तिगत मुलाकातें की हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी और प्रशिक्षण पहुँचाया जा सके। इन कार्यक्रमों में किसान अपनी समस्याएँ विशेषज्ञों से साझा करते हैं और जलवायु-अनुकूल तकनीकों को सीधे देख और सीख पाते हैं।

मैदान में शोध, प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन और सभी हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से यह पहल किसानों को पर्यावरण-अनुकूल और संसाधन-संरक्षण करने वाली खेती अपनाने के लिए प्रेरित करती है। इसका उद्देश्य गन्ने की पैदावार बढ़ाने के साथ-साथ अयोध्या क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन और दीर्घकालिक टिकाऊपन का एक ऐसा मॉडल विकसित करना है, जिसे अन्य जगहों पर भी अपनाया जा सके।

CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR
AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

(CEASI), Unit No. 101, First Floor, Greenwoods Plaza, Block 'B' Greenwoods City, Sector-45, Gurugram, Haryana-122009

+91 74287 06078

info@cedsi.in

www.ceasi.in

@ceasi_india